नेब्रास्का के एक आदमी ने अपना 60वां जन्मदिन कुछ अनूठे अंदाज में मनाया। उसने एक विशालकाय कद्दू को खोखला करके नाव बनाई और मिज़ोरी नदी में 38 मील की दूरी तय की। उम्मीद है कि उसने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डुएन हैनसन, बैल्व्यू शहर के सार्वजनिक बोट डॉक्स से सुबह 7.30 बजे 846 पाउण्ड के कद्दू में बैठकर रवाना हुए और शाम 6.30 नेब्रास्का शहर पहुँचे। हैनसन ने अपने रिकॉर्ड बनाने वाले इस प्रयास के लिए बैल्व्यू के अधिकारियों को गवाह बनाया। कद्दू की नाव के पीछे नाव का नाम भी लिखा था, "एस.एस. बर्टा।" हैनसन की पत्नी, परिवार और नदी पर मौजूद उनके मित्रों ने इस यात्रा को रिकॉर्ड किया। कुछ तो सुरक्षा की दृष्टि से उनके पीछे भी गए। कद्दू की सबसे लम्बी यात्रा का पूर्व रिकॉर्ड 25.5 मील का है, जो 2018 में बना था। यह जानकारी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वैबसाइट पर है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की प्रवक्ता काईली गैलोवे ने कहा कि "वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हैनसन की एप्लीकेशन मिली है हम अभी प्रमाणों की जांच कर रहे हैं।" हैनसन नेब्रास्का में रहते हैं तथा बड़े-बड़े कद्दू व अन्य सब्जियां उगाना उनका शौक है।

'तेजस्वी यादव हमारे सी.बी.आई. अधिकारियों को लगातार धमकियां दे रहे हैं'

सी.बी.आई. ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाये

- **गौरतलब है कि, आई.आर.सी.टी.सी. घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और बिहार के उप-मुख्यमंत्री हैं। सी.बी.आई. ने कोर्ट में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की अपील की है।**
- **सी.बी.आई. ने कहा है कि, तेजस्वी यादव मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। सी.बी.आई. ने कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा कि, तेजस्वी यादव के बाहर रहने से इस मामले के कई गवाह प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में उनको दी गई राहत रद्द कर दी जाए।**

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। इण्डियन रेलवे केटरिंग सर्विसेज़ (आई.आर.सी.टी.सी.) घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया है। सीबीआई ने अदालत में याचिका दायर कर तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है।

सीबीआई का कहना है कि, तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और सी.बी.आई. के अधिकारियों बुरी तरह से धमकियां दे रहे हैं। अदालत ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। हालांकि, अभी अदालत ने यादव को जवाब देने के लिए तलब किया है। ज्ञात रहे कि आईआरसीटीसी घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और बिहार के उप-मुख्यमंत्री पद पर हैं।

तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी हैं। इस मामले में वो जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अब सीबीआई ने अदालत दलील पेश की है कि यह एक गंभीर मामला है। यादव मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। सीबीआई ने याचिका में यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के बाहर रहने से इस मामले के कई गवाह प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में यादव को दी गई राहत को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग इस मामले में आरोपी हैं। यह मामला राउज एवेंन्यू अदालत में चल रहा है। इसकी जांच सीबीआई के साथ ही ईडी भी कर रही है। इस मामले में आईआरसीटीसी के होटल के टेंडर में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था, जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से लालू के परिवार के सदस्यों को जमानत मिल गई थी, परंतु अब सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव प्रभावशाली पद पर हैं और मामले में हस्तक्षेप कर जांच प्रभावित कर रहे हैं।

सीबीआई ने याचिका में कहा है कि बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक प्रेसवार्ता में खुलेआम सीबीआई अधिकारियों को धमकी भरे अंदाज में संदेश दिया है, क्योंकि इस समय वह एक प्रभावशाली पद पर हैं ऐसे में उनके द्वारा कही गई बातें जांच को प्रभावित कर सकती हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि यादव ने यह प्रेसवार्ता बिहार में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर की थी।

कांग्रेस में लोकतंत्र है या परिवारवाद: यहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा?

पी.सी.सी. सदस्यों की सूची में पिता-पुत्र, पति-पत्नी, पिता-पुत्री, मां-पुत्री की जोड़ियां शामिल हुई

- **जबकि, लोकसभा में हार के बाद राहुल गांधी ने परिवारवाद से पीछा छुड़ाने के लिए कहा था कि, अब गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा।**
- **लेकिन, कांग्रेस के राजस्थान के नेताओं ने राहुल गांधी के कहने के बिल्कुल विपरीत परिवारवाद को जमकर बढ़ावा दिया।**

जयपुर, 17 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस पर परिवारवाद का ऐसा ठप्पा लगा है कि इसका पीछा छुड़ाने के लिए खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के दौरान कहा था कि आने वाला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। लगता है कि राहुल गांधी के यह कहने के बावजूद कांग्रेस के नेता इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। यही कारण है कि राजस्थान में जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस सदस्यों के नाम सामने आए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही हो गई है, जहां राजा का बेटा राजा बनता है।

प्रदेश कांग्रेस के लगभग 60 से ज्यादा सदस्य ऐसे हैं, जो पूरी तरह से परिवारवाद का चोला पहनकर सदस्य बने हैं। इस सूची के जाहिर होने से पहले ही स्पष्ट हो गया है कि उदयपुर में जो डिक्लेरेशन सामने आया था, उसकी धज्जियां राजस्थान में ही उड़ा दी गई है।

राजस्थान में नेताओं ने जमकर परिवारवाद चलाते हुए अपने परिवारजनों को प्रदेश कांग्रेस सदस्य बनाया है और इनमें छोटे से लेकर बड़े, सभी नेता शामिल हैं। अपने पारिवारिक सदस्यों को पीसीसी सदस्य बनाने के पीछे नेताओं की मंशा यह भी है कि अगला विधानसभा चुनाव अपने परिवार में से ही किसी को लड़ाएं। ऐसे में कांग्रेस में लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी चाहे जितनी भारत जोड़ो यात्रा कर ले, लेकिन कांग्रेस के यह नेता चाहते ही नहीं कि कांग्रेस के साथ कोई जुड़े।

राजस्थान से परिवारवाद की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां खुद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश कांग्रेस के सदस्य हैं वहीं उनके पुत्र एवं लोकसभा में पहले ही उम्मीदवार बनाकर राजनीति में उतार दिए गए वैभव गहलोत को भी पीसीसी सदस्य बनाया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के दोनों ब्लॉक से खुद को और अपने बेटे बालेंदु को सदस्य बनाया है।

दौसा से मंत्री मुरारी लाल मीणा ने खुद को और अपनी पत्नी सविता मीणा को सदस्य बनाया है। इसी तरह से जोधपुर जिला प्रमुख लीला मदेरणा पीसीसी सदस्य बनी है, तो उनकी विधायक पुत्री दिव्या भी पीसीसी सदस्य बनी हैं। इसी तरह सरकारी उप सचेतक महेंद्र चौधरी खुद पीसीसी सदस्य बने, तो पत्नी सुनीता चौधरी को भी पीसीसी सदस्य बना लिया। इसी तरह से आलोक बेनीवाल निर्दलीय विधायक होने के वजह से खुद सदस्य नहीं बन सकते थे, तो सरिता बेनीवाल को पीसीसी सदस्य बना दिया। वहीं पाली से सांसद का चुनाव लड़ चुके बद्रीराम जाखड़ खुद भी पीसीसी सदस्य बने हैं, तो उनकी बेटी मुन्नी गोदारा भी पीसीसी सदस्य हैं।

करणपुर से विधायक गुरमीत कुन्नर खुद भी पीसीसी सदस्य हैं तो उन्होंने अपने बेटे रूबी कुन्नर को भी पीसीसी सदस्य बना दिया है। विधायक बाबूलाल बैरवा ने अपने बेटे अवधेश को पीसीसी सदस्य बना दिया, तो निर्दलीय बाबूलाल नागर ने भी अपने बेटे विकास को पीसीसी सदस्य बना दिया। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद पीसीसी सदस्य बनने के स्थान पर अपने पुत्र सागर शर्मा को पीसीसी सदस्य बनाया है।

वही मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने छोटे भाई की पत्नी रेखा कटारिया को पीसीसी सदस्य बना दिया है। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए मंत्री राजेंद्र यादव ने भी अपने बेटे मधुर यादव को पीसीसी सदस्य बनाया है। विधायक मीना कंवर ने अपने पति उम्मेद सिंह को पीसीसी सदस्य बनाया है। इसी तरह से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा को पीसीसी सदस्य बनाया गया है।

इसी लाइन पर चलते हुए विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने अपने बेटे अमित बुड़ानिया को पीसीसी सदस्य बनवाया है। वैसे तो जहां सचिन पायलट पीसीसी सदस्य बने हैं, वही उनकी मां रमा पायलट भी पीसीसी सदस्य बनी है, लेकिन सचिन पायलट जहां दो बार संसद सदस्य होने के अलावा वर्तमान में विधायक हैं, तो उनकी मां रमा पायलट भी पहले विधायक और सांसद रह चुकी हैं। इसके बावजूद उन्हें भी परिवारवाद की सूची में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा विधायक विनोद चौधरी ने अपने बेटे को पीसीसी सदस्य बनाया है।

इसी तरह से मंत्री परसादी लाल मीणा ने अपने बेटे कमल मीणा को पीसीसी सदस्य बनाया है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम है, जहां नेताओं ने अपने परिवार को राजनीतिक विरासत सौंपने का प्रयास किया है।

'भारत जोड़ो यात्रा से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उत्तर प्रदेश में केवल दो दिन गुजारेगी। येचुरी ने जोर देते हुये कहा कि अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करना कांग्रेस का अपना अन्दरूनी मामला हैं।

पार्टी के पोलित ब्यूरो की दो दिन की मीटिंग के बाद, उन्होंने दृढ़ तापूर्वक कहा कि वामंपथी दलों के कांग्रेस की यात्रा में शामिल न होने को कोईमहत्व नहीं दिया जाये, क्योंकि हर पार्टी के अपने कार्यक्रम होते हैं।

उन्होंने कहा कि आज धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक दलों के संगठित प्रयास जरूरी है ताकि सत्तारूढ़ भाजपा के हिन्दुत्व एजेंडा को रोका जा सके। येचुरी ने जोर देते हुये कहा कि सभी दलों को, स्थानीय स्तर पर भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर फोकस करते हुये, राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होगा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा हिन्दू एजेंडा तथा साम्प्रदायिकता पर जोर दिये जाने को रोकने के लिये, सभी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतान्त्रिक दलों के संगठित प्रयासों का समय आ गया है।

सी.पी.आई. (एम) नेता ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुये कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष करती है, लेकिन उनकी पार्टी को, भाजपा से लड़ने के लिये, राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में कोई परेशानी नहीं हैं।

डब्ल्यु.एच.ओ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होकर 5 हजार 747 होने के उपरांत यह सिफारिश सामने आई। शनिवार को देश में 29 जनों की करोना से मौत हुई। इसमें केरल में कल मरे 13 जनों की संख्या भी शामिल है। कर्नाटक में आज सुबह 8 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 4 लोगों की मौत की खबर है।

इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र का नम्बर है जहां इस बीमारी से दो-दो जनों की मौत हुई, जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडीशा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में एक-एक जने की मौत हुई। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5 लाख 28 हजार 302 हो गई है। भारत में इसके एक्टिव केस बढ़कर 46 हजार 848 हो गए, जबकि रिकवर हुए मरीजों की संख्या 4 करोड़ 39 लाख 53 हजार 374 है जिससे रिकवरी रेट 98.71 प्रतिशत हो गई है। डेली पॉज़िटिविटी रेट 1.69 प्रतिशत और वीकली रेट 1.74 प्रतिशत रही।

करोना वैक्सीनेशन के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अब तक 216.14 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटों में लगाई गई 23.92 लाख वैक्सीन्स शामिल हैं। अब तक 89.12 प्रतिशत टैस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें पिछले 94 घंटों में किए गए 3.40 लाख टैस्ट शामिल हैं।

प्रदेश अध्यक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। सभी नेताओं ने हाथ खड़े करके राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताकर सियासी तौर पर मैसेज देने का प्रयास किया। गहलोत ने खुद सदस्यों की मंशा रखी, इसलिए सियासी तौर पर इसका महत्व है। गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए हाथ खड़े करवाकर मुद्दे को हवा देने का प्रयास किया है कि सभी लोग राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बार फिर अशोक गहलोत की यह मंशा भी निकल कर आ रही है, जिसमें कि वह बार-बार ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। जबकि पिछले सप्ताह ही खुद अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि यदि आलाकमान और सोनिया गांधी कहेगी, तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। अब प्रदेश कांग्रेस सदस्यों की बैठक में उनकी ओर से प्रदेश रिटर्निंग अधिकारी के जाने के बाद सदस्यों से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मंशा पूछने को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

इस बैठक में 400 में से आधे सदस्य भी मौजूद नहीं रहे और जानकारी के मुताबिक करीब 175 सदस्य ही इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चूंकि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉ बी डी कल्ला को छोड़कर सचिन पायलट, नारायण सिंह, डॉ चंद्रभान, डॉ गिरिजा व्यास बैठक में मौजूद नहीं थे। वहीं सरकार के कई मंत्री भी बैठक में मौजूद नहीं थे।

अमेरिकी मीडिया में प्र.मंत्री मोदी की बढ़ा-चढ़ाकर तारीफें छपीं

वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्र.मंत्री की राष्ट्रपति पुतिन को दी गई सीख को लीड बनाकर पेश किया

- **द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया, भारत के नेता ने पुतिन को बताया कि, यह दौर युद्ध का नहीं है। अखबार ने लिखा है कि, बैठक का लहजा मित्रवत था और दोनों नेताओं ने अपने पुराने साझा इतिहास का जिक्र किया। मोदी के टिप्पणी करने से पहले पुतिन ने कहा कि, वह यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं को समझते हैं।**
- **वॉशिंगटन पोस्ट ने तो इस घटना को और एक कदम बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, इस न्यूज पेपर ने लिखा, मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा कि, आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में पहले फोन पर भी बातचीत की है। इसमें कहा गया कि, इस निंदा के कारण पुतिन सब तरफ से अत्यधिक दबाव में आ गए हैं।**

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को जमकर तारीफ की। यह सराहना रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन को पीएम मोदी की ओर से दी गई सीख को लेकर हुई। मोदी ने पुतिन से शुक्रवार को कहा था कि यह यूक्रेन में युद्ध करने का समय नहीं है। दरअसल, मोदी और पुतिन के बीच उज्बेकिस्तान के समरकंद में बातचीत हुई, जिसे अमेरिकी मीडिया ने बड़ी कवरेज दी है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने टाइटल दिया, मोदी ने यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन को फटकार लगाई। इस न्यूजपेपर ने लिखा, मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा... आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है। इसमें कहा गया कि इस निंदा के पुतिन सब तरफ से अत्यधिक दबाव में आ गए हैं।

पुतिन ने मोदी से कहा, मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपका रुख जानता हूं, मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं, जिनके बारे में आप बार-बार बताते रहते हैं। हम इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, विरोधी पक्ष यूक्रेन के नेतृत्व ने बातचीत प्रक्रिया छोड़ने का ऐलान किया। उसने कहा कि वह सैन्य माध्यमों से यानी युद्धक्षेत्र में अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है। फिर भी, वहां जो भी हो रहा है, हम आपको उस बारे में सूचित करते रहेंगे। यह द वाशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स के वेबपेज की मुख्य खबर थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया, भारत के नेता ने पुतिन को बताया कि यह युद्ध का दौर नहीं है। उसने लिखा, बैठक का लहजा मित्रवत था और दोनों नेताओं ने अपने पुराने साझा इतिहास का जिक्र किया। मोदी के टिप्पणी करने से पहले पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं को समझते हैं। न्यूजपेपर ने कहा, मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग की यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन के साथ पहली आमने-सामने की बैठक के एक दिन बाद टिप्पणियां कीं।

ज्ञानवापी मस्जिद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पक्ष प्लेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट 1991 को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, जिसके तहत 1947 के बाद से सभी धर्मस्थलों के विवाद को खारिज कर दिया गया, सिर्फ अयोध्या को इससे अलग रखा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के (ए.आई.एम.पी.एल.बी.) के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि जिला जज ने 1991 के कानून का उल्लंघन किया है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिवार्य करार दिया था। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि जिला जज ने 1991 के कानून की उपेक्षा की और उन याचिकाओं को खारिज करने की बजाय स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि जिला जज का आदेश अंतिम नहीं है। मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 1991 के कानून के क्रियान्वयन के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने जिला जज के फैसले का विश्लेषण करने के लिए कई वकीलों से बात की है। ज्ञानवापी मस्जिद - श्रृंगार गौरी केस में वादी रेखा पाठक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है कि कोई भी फैसला देने से पूर्व उसका पक्ष सुना जाए।

अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई?

हैदराबाद, 17 सितम्बर। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टी आर एस) नेता गोसुला श्रीनिवास ने हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के सामने अपनी कार खड़ी कर दी। यह देख होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम ने गाड़ी वहां से हटवा दी। वहीं, श्रीनिवास ने उनके ऊपर दबाव डालने का आरोप लगाया है। साथ ही उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी हुई है।

टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास ने कहा, मेरी कार को जिस तरह से रोका गया, उसे देखकर मैं टेंशन में आ गया। पुलिस अधिकारियों से इसकी मैं शिकायत करूंगा। उन्होंने मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ की है।

यह एक गैर-जरूरी तनाव है जिसे जानबूझकर खड़ा किया गया। मालूम हो कि गृह मंत्री शाह ने शनिवार को हैदराबाद मुक्ति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद की मुक्ति का श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को दिया। उन्होंने वोट बैंक की राजनीत के कारण मुक्ति दिवस मनाने के वादे से मुकर जाने वालों पर निशाना साधा।

निज़ाम शासन से मुक्ति दिवस या...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्ष होने वाले राज्य विधान सभा चुनाव तथा 2024 के आम चुनावों में होने वाली टक्कर को मद्देनजर रखे हुये था। आज का दिन दोनों पक्षों द्वारा पूरे वर्ष किये जाने उन आयोजनों का शुभारम्भ था, जिनमें शाब्दिक आतिशबाजी पूरे वर्ष, एक वर्ष के अन्दर ही होने वाले विधानसभा चुनावों तक, देखने को मिलती रहेगी। 1948 में आज के दिन, अर्थात् 17 सितम्बर को ही, तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही के बाद हैदराबाद स्टेट, जहाँ उस समय निज़ाम का शासन, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था।

के.सी.आर. तथा उनकी सरकार पर अमित शाह के चुभते हुये हमले के जवाब में, के. चन्द्रशेखर राव ने अपनी आक्रामक प्रतिक्रिया में भाजपा को एक ऐसी विभाजनकारी ताकत बताया, जो राज्य की शान्ति एवं भाईचारे का नष्ट करने के लिये कमर कसे हुये हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि भाजपा की हर योजना पराजित एवं नेस्तानाबूद कर दी जायेगी। आज के दिन, जो 1948 में हैदराबाद के भारतीय संघ में शामिल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, के.सी.आर. ने कहा कि भाजपा का आयोजन उसके "विभाजक एजेंडा" से जुड़ा हुआ है। "तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे" मनाते हुये, मुख्यमंत्री ने नामपल्ली के पब्लिक गार्डन्स में राष्ट्र ध्वज फहराया, और उससे कुछ ही दूरी पर, केन्द्रीय गृहमंत्री ने भी राष्ट्रध्वज फहरा कर "हैदराबाद लिबरेशन डे" बनाया।

राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुये, केन्द्रीय गृहमंत्री ने आरोप लगाया कि इस जगह (तेलंगाना) के शासक वोट बैंक की राजनीति के कारण आज के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की हिम्मत नहीं कर सकते। प्रसंगवश बता दे कि मुख्यमंत्री ने मुक्ति दिवस का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने आमन्त्रण स्वीकार करने के स्थान पर, यह सवाल कर डाला कि "भाजपा 9 नवम्बर को गुजरात की जूनागढ़ रियासत के भारत में हुये एकीकरण का जश्न क्यों नहीं मनाती, हैदराबाज पर ही फोकस करना क्यों चाहती है।" भाजपा, जिसने पिछले आम चुनाव में तेलंगाना से 4 लोकसभा सीटें जीती थीं, इस बार और भी अच्छा प्रदर्शन करने की सुखद कल्पनाओं में खोई हुई है, क्योंकि वहाँ अब कांग्रेस कमजोर हो गई है। वस्तुतः भाजपा नेता यह मानकर चल रहे हैं कि टी.आर.एस. और कांग्रेस भविष्य में मिल जायेंगी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे लोगों से मिलते समय, अपनी बातचीत में इस बात को जरूर कहें।

आज के भाषण, जो साफ तौर पर एक चुनावी भाषण था, में के.सी.आर. ने उनकी सरकार द्वारा पिछले आठ साल में किये गये काम बार-बार गिनाये तथा लोगों का स्मरण दिलाया कि राज्य को अपने अधिकारों गरिमा एवं स्वाभिमान की खातिर किस तरह लड़ना पड़ा था।

के.सी.आर. ने कहा, "हमारे सामने वैसी स्थिति फिर से नहीं आनी चाहिये। ....आपको तेलंगाना दिलाने वाले व्यक्ति के रूप में, आपको इस बात के प्रति सचेत करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है कि इस प्रदेश को उसी दुर्व्यवस्था की स्थिति में मत पहुँच जाने देना।.........हमें तरक्की की ओर आगे बढ़ ते रहने की जरूरत है।" उन्होंने "बाँटने के एजेंडा" वाले दल के खिलाफ आगाह करते हुये कहा कि ऐसे लोगों से होशियार रहिये, जो धर्म का दुरूपयोग कर रहे हैं तथा लोगों को बाँट रहे हैं। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुये कहा कि वे आगे के संघर्ष के लिय तैयार रहें।

अपनी लगातार जीत से चिंतित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। इनमें हथियारों के अधिक सहयोग और रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का जिक्र किया गया है। यह घोषणा ज़ैलेन्स्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंद्रीय यर्माक और नाटो के पूर्व महासचिव आंद्रे फो रॉस्मसन ने की। यर्माक ने कहा "हमें एक ऐसी मिलिटरी फोर्स की जरूरत है जो आक्रमणकारी को अपूरणीय क्षति पहुंचा सके। सुरक्षा गारंटियों का उद्देश्य ऐसी शक्ति बनने के लिए मदद पाना है।"

प्रकट रूप से, कीव द्वारा प्रस्तुत पैकेज मॉस्को को नागवार गुजरा है। यूक्रेन पर किया गया सुनियोजित आक्रमण इतना अधिक श्रमसाध्य रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और उनके अधिकारियों ने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। हाल ही के हफ्तों में गंभीर क्षति पहुंचने के बावजूद रूस अब भी स्वयं को पूर्वी यूरोप की एक पूर्व प्रतिष्ठित शक्ति के रूप में देखता है और अपनी शक्ति के सामने आने वाली किसी भी चुनौती के प्रति उसने कठोर प्रतिक्रिया दी है। रूस की सुरक्षा-परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव के अनुसार कीव की मित्र मण्डली ने "सुरक्षा गारंटियों" के एक ऐसे प्रोजेक्ट की आशंका प्रकट कर दी है जो तीसरे विश्व युद्ध की एक प्रस्तावना है।

उन्होंने कहा कि "वास्तव में, यूक्रेन के नाज़ियों को कोई भी किसी प्रकार की गारंटी नहीं देगा, आखिरकार ऐसा करना नाटो संधि में अनुच्छेद 5 को लागू करने के समान है। मेदवेदेव ने आगे कहा कि "यदि ये बेवकुफ इस तरह के हथियारों से कीव सरकार को निरंतर उकसाना जारी रखेंगे तो आज नहीं तो कल सैन्य अभियान अन्य स्तर पर पहुंच जाएगा।" "उसके बाद सब कुछ जल उठेगा। उनके लोग पूर्णतया दु:खी हो जाएंगे, उनकी भूमि सचमुच जल उठेगी और पत्थर भी पिघल जाएंगे। हमें भी भारी क्षति होगी। यह हर किसी के लिए बहुत बुरा होगा।" गत फरवरी माह में किए गए आक्रमण के लिए यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की चुनौती को प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है और पश्चिमी देशों को ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत करने से पूर्व बहुत ध्यानपूर्वक सोचना होगा, जिसे तीसरे विश्व युद्ध के पूर्व संकेत के रूप में देखा जाता हो।

नीतीश-सोनिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगले सप्ताह या 25 सितम्बर के आसपास मुलाकात का समय मांगा है जिसमें वे अपनी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। वे इण्डियन नैशनल लोकदल के संस्थापक और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल की जयंती में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इस उपलक्ष में अगले रविवार 25 सितम्बर को एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में कई विपक्षी नेता एकत्रित होंगे क्योंकि आई.एन.एल.डी. के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश कुमार, शरद पवार, अखिलेश यादव और डॉ. फारुख अब्दुल्लाह को बुलाया है। नीतीश इन नेताओं से पहले ही मिल चुके हैं तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और वामपंथी नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश खेमे के सूत्रों ने कहा कि वे सोनिया से मुलाकात कर उन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी. आर., दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तथा प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मतभेद दूर करने के लिए समझाएंगे। गत यात्रा में नीतीश राहुल गांधी से मिल चुके हैं पर सोनिया से नहीं मिल पाए थे क्योंकि तब वे विदेश में थीं।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908